दसवाँ दीक्षांत समारोह

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

24 दिसम्बर, 2016

श्री प्रभुलाल सैनी
माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार

उद्‌बोधन

माननीय श्री कल्याण सिंह जी, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाद्यिपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, माननीय श्री गुलाबचन्द जी कटारिया, गृहमंत्री, राजस्थान सरकार, डॉ. उमा शंकर शर्मा, कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, डॉ. अजय शंकर पाण्डे, ओ.एस.डी., माननीय राज्यपाल, राजस्थान, प्रबंधन मंडल व शैक्षणिक परिषद् के माननीय सदस्य, अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, कुलसचिव, शिक्षक एवं कर्मचारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधि, विद्यार्थीगण व उनके अभिभावक, अन्य समस्त महानुभावों, भाइयों एवं बहनों।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस पावन भूमि पर आकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं ऐसे महान पुरूष को नमन करता हूँ।

मैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के दसवें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर सर्वप्रथम स्वर्ण पदक एवं उपाधियाँ प्राप्त करने वाले छात्रों व छात्राओं को बधाई देता हूँ। किसी भी शिक्षण संस्थान की पहचान उसके छात्रों से होती हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त छात्र–छात्राएँ देश व विदेशों में कार्यरत हैं। मैं उपाधि प्राप्त छात्रों व छात्राओं से आशा करता हूँ कि वे कृषक समुदाय की सेवा कर राष्ट्र के कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे।

राजस्थान क्षेत्रफल तथा कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है। राजस्थान की 54 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर हैं तथा लगभग 1.23 करोड़ लोग सीधे कृषि से जुड़े हैं। राजस्थान में कृषि विकास तथा किसानों की खुशहाली के लिए राजस्थान सरकार, कृषि अनुसंधान, कृषि तकनीकों के प्रसार तथा गाँवों में किसानों के

चहुँमुखी विकास के लिए सतत् प्रयासरत है। राजस्थान के कृषि विकास में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की अहम भूमिका है। राजस्थान के मेवाड़ अंचल के 7 जिलों – भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चितौड़गढ तथा प्रतापगढ़ में कृषि विकास में इस विश्वविद्यालय का विशेष योगदान है।

मेवाड़ आँचल का अधिकतर क्षेत्रफल पहाड़ी तथा आदिवासी बाहुल्य होने के कारण कृषि विकास की परिस्थितियाँ राजस्थान के अन्य जिलों से भिन्न हैं। राज्य की 54 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या मेवाड़ आँचल में रहती है ओर इस क्षेत्र के 79 प्रतिशत किसान छोटी जोत वाले हैं। यहाँ सिंचाई के साधन सीमित हैं तथा लगभग 46 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र है।

राजस्थान में प्रत्येक तीन में से दो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। प्राकृतिक एवं मौसमीय विषम परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान के किसानों ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चेम्पियन किसान के रूप में पहचान बनाई है। इसके लिए कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार तथा ग्रामीण विकास की नीतियों एवं योजनाओं में सतत परिवर्तन कर कृषि विकास एवं कृषक कल्याणकारी बनाने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयासरत है।

वर्तमान में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि में उत्पादकता, टिकाऊपन एवं नवाचार पर फोकस किया जा रहा है जिसके तहत नीतिगत, तकनीकी एवं ढांचागत विकास के पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है।

कृषि में कटाई उपरन्त हानि को कम करना, कृषि आधारित औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन, कृषि विपणन में सुधार, ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता के कृषि आदन एवं उत्पाद की उपलब्धि तथा जलवायु जोखिम में किसान आजीविका सुरक्षा जैसी योजनाओं एवं कार्यों द्वारा राज्य में कृषि विकास एवं किसानों की आय में वृद्वि करने पर जोर दिया जा रहा है।

फसल, फल तथा सब्जी उत्पादन की दृष्टि से मेवाड़ का राजस्थान में विशेष स्थान है। प्रदेश की कुल मक्का उत्पादन का 82 प्रतिशत, उड़द का 40 प्रतिशत, सोयाबीन का 36 प्रतिशत, अरहर का 61 प्रतिशत तथा गेहूँ का 10 प्रतिशत हिस्सा मेवाड़ के जिलों में उत्पादन होता है।

फलों में राज्य में आम का लगभग 52 प्रतिशत क्षेत्रफल पपीता का 43 प्रतिशत, सीताफल का 92 प्रतिशत, अमरूद का 16 प्रतिशत तथा आँवला का 18 प्रतिशत क्षेत्रफल दक्षिण राजस्थान में है। विश्वविद्यालय द्वारा आम तथा अमरूद की किस्मों तथा प्रबंधन तकनीकों पर अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना के तहत तथा सीताफल प्रसंस्करण पर विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुसंधान से आदिवासी किसानों को सीताफल प्रसंस्करण द्वारा अधिक आय अर्जित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्जी, फल तथा फलों पर ''उत्कृष्टता केन्द्र'' खोले जा रहे हैं जिनके द्वारा उद्यानिकी क्षेत्र में नई उत्पादन तकनीकों का किसानों तक प्रसार किया जायेगा।

बढ़ती लागत तथा सही समय पर श्रम की उपलब्धता आज किसानों के सामने एक चुनौती है। इसके लिए कृषि कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत मशीनों का विकास तथा कस्टम हाईरिंग केन्द्रों का स्थापना की जा रही है। इसके लिए हमें किसानों का सहयोग आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक बड़े एवं महंगी मशीनों कस्टम हाइरिंग केन्द्रों पर रखी जा सके तथा किसान समूह के माध्यम स्वयं इनका प्रबंधन कर सकें। दक्षिण राजस्थान में आदिवासी किसानों के लिए कस्टम हाइरिंग केन्द्रों की स्थापना पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कस्टम हाइरिंग केन्द्र होने चाहिए।

मेवाड़ में चार वर्ष में एक बार सूखा पड़ने से मक्का तथा अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विश्वविद्यालय के बारानी अनुसंधान केन्द्र, भीलवाड़ा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय में चल रहे तीन जलवायु अनुकूलित कृषि परियोजनाओं के माध्यम से सूखा प्रबंधन, जल संरक्षण, मौसम पूर्वानुमान द्वारा फसल प्रबंधन, कन्टीन्जेन्सी फसल योजना, चरागाह प्रबंधन तथा कस्टम हायरिंग केन्द्र आदि तकनीकों द्वारा विपरीत मौसम में फसल में कम से कम खराबा की तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इन तकनीकों को कृषि विभाग तथा नरेगा कार्य से जोड़कर प्रोजेक्ट के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

मिट्टी तथा मानव स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ने से शुद्व खाद्य पदार्थों की बाजार मांग बढ़ रही है। जैविक खेती में और अधिक अनुसंधान तथा किसानों को सही तरीके से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने डूंगरपूर जिले को राज्य का पहला 'जैविक जिला' घोषित किया है। शीघ ही राज्य सरकार द्वारा राज्य की जैविक नीति की घोषणा की जायेगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक ब्लॉक विकसित किये जा रहे है। मुझे यह जानकर खुशी है कि वर्ष 2015 में उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर की जैविक खेती नेटवर्क परियोजना का नया केन्द्र मिला है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की जैविक खेती पैकेज विकसित की गई है। इससे दक्षिणी राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

राज्य में नवाचारों पर अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जा रहा हैं। इसी क्रम में ड्रेगन फ्रूट, पिस्ता व कनकुआ की खेती प्रदेश में शुरू की जा रही हैं। प्रदेश में जैतून, खजूर, ड्रेगन फ्रूट, पिस्ता के उत्पादन की अपार संभावनाऐं हैं। राज्य की शुष्क व अर्द्व शुष्क जलवायु इनकी खेती के लिये उपयुक्त है। जैतून की खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राजस्थान को क्वालिटी कार्ड अवार्ड 23 नवम्बर, 2015 को लंदन में प्रदान किया गया। प्रदेश पूरे देश में जैतून उतपाददित करने वाला पहला राज्य बना गया है। राजस्थान का जैतून तेल विश्व में सबसे उच्च गुणवत्ता का है। जैतून के तेल की रिफाइनरी लुणकरणसर में स्थापित की गई है।

राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के विकास एवं प्रसार को निवेश के साथ जोड़ा जा रहा है जिससे कृषि विकास को टिकाऊ बनाया जा सके और कृषि में 'सदाबहार क्रान्ति' के विभिन्न आयामों को मूल स्वरूप में किसानों तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए राज्य में नीतिगत बदलाव द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रमोशन नीति 2015, राज्य जलनीति, उर्जा प्रबन्धन, फार्म मशीनीकरण, कान्ट्रेक्ट खेती, निर्यात प्रबंधन, कृषि लोजिस्टिक, डेयरी, ऊन उत्पादन, जैविक कृषि को प्रात्साहन, कृषि नवाचार में स्टार्ट–अप आदि पहलुओं पर सकारात्मक परिवर्तन कर कृषि में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा 9–11 नवम्बर, 2016 को आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीमीट (ग्राम) का उद्देश्य कृषि में नवाचार निवेश तथा पार्टनरशीप को बढ़ावा देकर कृषि के चहुँमुखी विकास को बढ़ावा देना है जिससे किसानों तक नई तकनीकें पहुँचाने का अवसर मिला। इससे उत्पाद का मूल्य अधिक मिलने तथा विश्वस्तर पर राजस्थान के किसानों को आयात–निर्यात एवं तकनीकी उपलब्धता के नए मार्ग खुले है एवं उद्योग स्थापित करने के नए अवसर प्राप्त हुए हैं।

कृषि उत्पादन, प्रकृति एवं मानसून के कारकों पर निर्भर होता है अतः किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना से जुड़कर जोखिमों का प्रबंधन की व्यवस्था करना अतिआवश्यक है। जिसमें तूफान, ओला–वृष्टि, चक्रवात, अंधड़, बाढद्य, जलभराव, सूखा, पाला, बिजली गिरना, कीट व रोग, आग इत्यादि आपदाऐं प्रमुख है। इसके अलावा अगर बीमित किसान बुवाई/रोपाई के लिये खर्च करने के बावजूद खराब मौसम की वजह से बुवाई/रोपाई नहीं कर सकते तो वे बीमित राशि के 25 प्रतिशत तक नुकसान का दावा ले सकेगें। नई योजना में खरीफ की फसलों के लिये 2 प्रतिशत व रबी के लिये 1.5 प्रतिशत बीमा दर रखी गई। इसके अलावा व्यवसायिक व बागवानी फसलों के लिये प्रीमियम की दर अधिकतम 5 फीसदी रखी गई हैं। इस योजना में फसलों में नुकसान के सही आंकलन व शीघ्र भुगतान के लिये सैटेलाइट तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। मैं इस अवसर पर किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस लाभकारी योजना को शत–प्रतिशत किसान अपनायें।

दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र अधिक है तथा आदिवासी बहुल हैं यहाँ के किसानों के पास संसाधन सीमित है अतः कम लागत व सामूहिक संसाधन प्रबंधन वाली तकनीकों एवं योजनाओं पर बल दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में जीरो बजट खेती, जैविक कृषि, कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा मशीनीकरण, बायोगैस, समन्वित कृषि पद्वति, प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा विपणन, स्वयं सहायता समूहों का विकास तथा जनजाति आधारित विशेष शेजनाओं द्वारा कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मोबाइल तथा इन्टरनेट क्रान्ति ने कृषि उत्पादन एवं बाजार प्रबंधन पर गहरा प्रभाव डाला है। राज्य में डिजिटलीकरण कर कृषि विस्तार को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस विखर को ध्यान में रखते हुए। गांवों के क्षेत्रों के दूरदराज तक बुनियादी सुविधाओं को

पहुंचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर देशव्यापी कार्यक्रम विकसित हो रहा है, और रिकॉर्ड का एक बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है जिससे कि इंटरनेट पर इसकी सरल और विश्वसनीय पहुँच को आसान बनाया जा सके। इनमें इंटरनेट, टच स्क्रीन कियोस्क, कृषि क्लीनिक, निजी खोखे, मास मीडिया, सामान्य सेवा केंद्र, किसान कॉल सेन्टर, विभागीय कार्यालयों में एकीकृत प्लेटफार्म और पिको प्रोजेक्टर तथा विभिन्न उपकरणों के साथ सुसज्जित विस्तार कर्मियों की आउटरीच शामिल है। हालांकि, मोबाइल टेलीफोन के साथ (इंटरनेट के साथ या बिना) कृषि विस्तार के सबसे शक्तिशाली और सर्वव्यापी उपकरण है।

नई पीढ़ी को कृषि से जुड़ने के अवसर बढ रहे हैं। मशीनीकरण, आटोमाटाइजेशन, ई–कॉमर्स, जैविक उत्पाद, उत्पादकता समूह, उत्पादकता कम्पनी तथा इको–ट्यूरिज्म आदि नए विकास के आयामों ने कृषि को नया स्वरूप दिया है।

मैं युवाओं से आहवान् करता हूँ कि हमें नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर एक अनुभूति और स्थिति मूल्यवान होती है। देश और समाज की प्रगति उसकी रचनात्मक में, उसके उकारात्मकता नजरियों में होती है। आपको कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा लेकर ज्ञान की प्रतिध्वनी का असर कृषि के चहुँमुखी विकास तक पहुँचाना है।

हमारे पास दो रास्ते हैं या तो हम दीप हो जाएं या आईना, जो उसे दोगुना कर देता है। तो आइए कुछ–कुछ सार्थक करें। धन से प्रेरित होकर नहीं मानवीय मूल्यों से प्रेरित होकर। क्योंकि बड़ी–बड़ी इनकम और महंगे साज–ओ–सामान के बजाय सार्थक संकल्प जीवन को अधिक प्रसन्न बनाते हैं। ना....यह जरूरी नहीं कि माझी की तरह हम पहाड़ काटें, लेकिन उत्सव की राह में पड़े छोटे–छोटे पत्थर तो हटा ही सकते हैं। न हो बड़े–बड़े परिवर्तन, लेकिन आशाओं के ऐसे छोटे–छोटे दीप तो हमारे ये सकंल्प जला ही सकते हैं।

तमस से ज्योति की ओर गमन की कामना करें। आखिर आदि ग्रंथों से आती 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की पुकार उत्सवधर्मिता की ओर बढ़ाया गया जीवन का पहला कदम है।

अतः मैं विश्वविद्यालय के प्रतयेक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप सभी यहाँ के गौरवशाली योगदान को कायम रखने में पूर्ण सहयोग देगें।